सहकारी समितियों द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार

***४०१. श्री द० ब० राजू :** क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य स्तर पर नियंत्रण रखने के लिये वर्तमान राष्ट्रीय आपातकाल में सहकारी समितियों के द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केन्द्र द्वारा तैयार की गई उपभोक्ता सहकारी समितियों की योजना के अन्तर्गत जो थोक भंडार संगठित किये गये हैं वे जरूरत पड़ने पर अपनी आवश्यकताओं को खरीद थोक में करने के लिये अपने ही राज्य के भीतर और अन्तर्राज्य स्तर पर विपणन और विधायन सहकारी समितियों के साथ सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे ।

(ख) चूंकि थोक भन्डार अभी अभी चालू किये जा रहे हैं अतः ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

[(a) The wholesale stores organised under the centrally sponsored scheme on consumers co-operatives would establish direct business relations with marketing and processing cooperatives within the state and at inter-state level for the bulk purchase of their requirements as and when necessary.

(b) Since the wholesale stores are just being started precise data are not available.]

Shri D. B. Raju: In the present national emergency are the co-operatives allowed to purchase from the open market to control the price-line? If so, are the co-operatives exempted from income-tax?

Shri Shyam Dhar Misra: The whole sale societies which will be established will be allowed to purchase from the open market as far as necessary and will also patronise the processing and marketing co-operatives, as far as possible.

Shri R. G. Dubey: May I know how many co-operative wholesale societies have been started in the various States in order to hold the price-line?

Shri Shyam Dhar Misra: By the end of the next financial year 200 wholesale societies are to be established; by the end of this financial year 70 wholesale societies are to be established. Out of these 70 societies, ten wholesale societies in Madras, Rajasthan and Delhi have already been established and others will come on the 26th of January.

श्री तुलसीदास जाधव : यह जो कोआपरेटिव स्टोर्स खुल रहे हैं उनसे जो माल बेचा जाता है वही माल जब प्राइवेट ओनर्स बेचते हैं तो वह सस्ता बेचते हैं और चूंकि वहां माल सस्ता मिलता है इसलिये गाहक उधर चले जाते हैं और कोआपरेटिव स्टोर्स में नुकसान होता है और उसके कारण वे बन्द होते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट इन कोआपरेटिव स्टोर्स को कुछ ऐसे आर्टिकिल्स देने वाली है जोकि बाहर प्राइवेट में न मिलें ।

श्री श्यामधर मिश्र : ये होलसेल स्टोर्ज और कन्ज्यूमर्ज स्टोर्ज इसलिये नहीं खोले जा रहे हैं कि माल सस्ता हो । अमल में उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अच्छा माल, अनएडल-ट्रेटिड माल, फेयर प्राइस पर मिल सके । इसके अलावा जो ड्रग्ज गवर्नमेंट कंट्रोल में हैं, उनके संबंध में गवर्नमेंट से बातचीत हो चुकी है । कपड़े के बारे में टैक्सटाइल कमिश्नर से बातचीत चल रही है । इसी तरह आयल के बारे में इंडियन आयल कम्पनी से बातचीत की जा रही है । ये चीजें इन होलसेल स्टोर्ज

से मिलेंगी, जिससे कीमत कुछ फेयर होगी और अच्छी चीजें मिल सकेंगी ।

Shri Sham Lal Saraf: May I know whether these wholesale co-operative stores will have branches or will supply consumer goods to the co-operative societies, or will they also purchase other agricultural products that will be available within their territory?

Shri Shyam Dhar Misra: They are principally to supply consumer goods. To the extent consumer goods are necessary they can purchase them from the producer society.

श्री विश्राम प्रसाद : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो डेफिसिट एरियाज हैं, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर प्राइसिज को बढ़ने से रोकने के लिये क्या विचार किया जा रहा है ?

श्री श्यामधर मिश्र इन होलसेल स्टोर्ज का ताल्लुक डेफिसिट एरियाज या नान-डेफिसिट एरियाज से कतई नहीं है । ये तो सप्लाई सोसायटीज होंगी, जो कि सामान प्रोक्योर करेंगी, जो कि सामान को डेफिसिट एरियाज में पहुंचायेंगी उन जगहों से, जो कि नान-डेफिसिट एरियाज हैं, जहां सामान बनते हैं । मिसाल के तौर पर हो सकता है कि कल लिवर ब्रदर्ज, बम्बई, से सामान लेना पड़े दिल्ली के लिये । हो सकता है कि आनन्द सोसायटी से बटर लेना पड़े राजस्थान के लिये । इसलिये इस बारे में डेफिसिट और नान-डेफिसिट एरियाज का प्रश्न नहीं उठता है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: How far have the Government decided to widen the area of preferences granted to the co-operatives *vis-a-vis* the private trade?

Shri Shyam Dhar Misra: Co-operatives are being given preference only with that end in view. They are able to supply goods at a fair price and the goods are unadulterated. The difference in the price factor may not be very much. As regards assistance from the Government, there are various forms of assistance already in the scheme.

Mr. Speaker: Next question. Could question No. 413 also be answered along with that?

An Hon. Member: That is silghtly different from this.

Mr. Speaker: All right; then that may be answered separately.

Agreement with Pakistani Ratings and Joint Steamer Companies

+

*402. Shri S. M. Banerjee:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Bishanchander Seth:

Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the agreement reached between the Pakistani Ratings and the Joint Steamer Companies has adversely affected the Indian employees;

(b) whether Indian employees numbering 6000 of Calcutta establishments have made a representation to Government in this regard;

(c) the steps taken to mitigate their hardships; and

(d) whether a representative has been included in four party comittee?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) and (c). The interests of the Indian employees are not adversely affected by the agreement between the Joint Steamer Companies and their Pakistani ratings. The question of mitigating any hardship resulting from the agreement to the Indian employees of the Companies does not, therefore, arise. A copy of the Memorandum of Settlement between the management of the Companies and the crew who